

संपादकीय

आस्था की सुरक्षा के लिए नई चुनौती

भारत में मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र भी हैं। विशेष रूप से अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद देशभर के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि किसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी या सुरक्षा में चूक जैसी घटना सामने आती है, तो उसका असर केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे धार्मिक तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी कारण जब किसी प्रमुख मंदिर में चोरी या वित्तीय अनियमितता की घटना सामने आती है, तो प्रशासन अन्य मंदिरों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा शुरू कर देता है। इसका उद्देश्य केवल अपराधियों तक पहुँचना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी होता है। मंदिरों में बढ़ती सुरक्षा की आवश्यकता देश के अनेक बड़े मंदिरों में प्रतिदिन लाखों रुपये का चढ़ावा आता है। त्योहारों, विशेष अवसरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। नकद दान के साथ-साथ सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ भी श्रद्धालु अर्पित करते हैं। ऐसे में इन मंदिरों की सुरक्षा किसी बैंक या अन्य महत्वपूर्ण संस्थान से कम चुनौतीपूर्ण नहीं रह जाती। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के उपयोग के बावजूद यदि निगरानी व्यवस्था में कहीं भी लापरवाही हो, तो चोरी या गबन जैसी घटनाएँ संभव हो सकती हैं। इसलिए केवल परिसीजीवी कैमरे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग की समीक्षा और सुरक्षा व्यवस्था का समय-समय पर ऑडिट भी आवश्यक है। प्रशासन की बड़ी सतर्कता- किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस और जिला प्रशासन सामान्यतः अन्य प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी आकलन करते हैं। इसमें कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है— सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनकी कार्यक्षमता। चढ़ावे की गिनती और सुरक्षित भंडारण की प्रक्रिया। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और उनकी जवाबदेही। प्रवेश एवं निकास द्वारों की निगरानी। दानपात्र खोलने का पारदर्शी व्यवस्था। रिकॉर्ड रखने और डिजिटल निगरानी की प्रणाली। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य श्रद्धालुओं के विश्वास को मजबूत बनाए रखना होता है। तकनीक बन सकती है सबसे बड़ी सुरक्षा- आज कई प्रमुख मंदिर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हाई-रिजोल्यूशन कैमरे, फेस रिकग्निशन, डिजिटल एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक प्रवेश, अलार्म सिस्टम और कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्थाएँ सुरक्षा को मजबूत बना रही हैं। इसके अलावा चढ़ावे की गणना में भी मशीनों और डिजिटल रिकॉर्डिंग का उपयोग बढ़ रहा है। इससे मानवीय त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना कम होती है तथा प्रत्येक प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। श्रद्धालु मंदिर में दान केवल धार्मिक भावना से नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चढ़ावे की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। नियमित ऑडिट, सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्ट, बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा और बहुस्तरीय निगरानी व्यवस्था से लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। यदि किसी मंदिर में वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी हो, तो चोरी या गबन की आशंकाएँ भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं मंदिरों की सुरक्षा केवल प्रशासन या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। मंदिर ट्रस्ट, कर्मचारी, स्वयंसेवक और श्रद्धालु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना देना, सुरक्षा नियमों का पालन करना और निगरानी व्यवस्था में सहयोग करना सामूहिक जिम्मेदारी है। किसी एक घटना के आधार पर सभी मंदिरों की व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं होगा। देश के अधिकांश मंदिरों में सुरक्षा और वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्थाएँ प्रभावी ढंग से संचालित होती हैं। फिर भी किसी भी घटना से सीख लेकर सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाना प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक कदम है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बड़े मंदिरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। समय-समय पर सुरक्षा ऑडिट, कर्मचारियों का सत्यापन, डिजिटल लेखा-जोखा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और नियमित प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना को कम कर सकती हैं। मंदिरों की सुरक्षा केवल संपत्ति की रक्षा का विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्रमुख मंदिर में चोरी की घटना सामने आती है, तो उससे सबक लेते हुए अन्य मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुदृढीकरण एक स्वाभाविक तथा आवश्यक प्रशासनिक कदम है। पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, जवाबदेही और जनसहभागिता के माध्यम से ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट बना रहे और मंदिर सुरक्षित, व्यवस्थित तथा विश्वसनीय धार्मिक केंद्र बने रहें।

राजीव शुक्ला - (संपादक)



मेघ -मेघ राशि आज आपको बातचीत और निर्णय लेने के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। कार्यक्षेत्र में पहले से अधूरे पड़े कार्य दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। व्यापार करने वाले लोगों को पुनः संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है, जबकि नए समझौते सोच-समझकर करना उचित रहेगा। पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा और पुराने मतभेद दूर होने के संकेत मिल सकते हैं। दायित्व जीवन में सहयोग बना रहेगा।

वृषभ-आर्थिक मामलों में आज संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए बजट पर विशेष ध्यान दें। व्यापार में पहले किए गए निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार में संयम रखना चाहिए।

मिथुन -आज किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें। कार्यक्षेत्र में पुराने अवसर दोबारा मिल सकते हैं, जिनका उचित लाभ उठाया जा सकता है। व्यापार में धैर्य बनाए रखना आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है।

कर्क -लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल माना जा सकता है। दूर स्थान या विदेश से जुड़े कार्यों में कुछ देरी संभव है। कार्यक्षेत्र में किसी भी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।

सिंह -आज मित्रों और सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखने से कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। व्यापार में अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है।

कन्या-कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ अपने कार्यों पूरे करें। व्यापार में पुराने शाहकों से लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में विश्वास और

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से आगरा में युवाओं के स्वावलंबन और स्वरोजगार की नई उड़ान

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' (डब्ल्यू।) राज्य के शिक्षित और कुशल युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार प्रदाता के रूप में विकसित करना है। इसके तहत प्रदेश सरकार युवाओं को अपने नए उद्यम, स्टार्ट-अप या सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए बेहद आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता और संसाधन उपलब्ध करा रही है, जिससे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को जमीनी स्तर पर एक नई मजबूती मिल रही है। यह अभियान उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को गति देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं का पलायन थमा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में आगरा जनपद में इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत प्रभावी ढंग से हो रहा है, जहां जिला प्रशासन और स्थानीय बैंक शाखाओं के सक्रिय सहयोग से युवाओं के सपने तेजी से साकार हो रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशिष्ट वित्तीय संरचना है, जो नए उद्यमियों के लिए शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती है। इसके अंतर्गत युवाओं को उद्योग और

सेवा क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि युवाओं को अपनी पूंजी के लिए साहूकारों या बैंकों की जटिल और महंगी ब्याज दरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। योग्य लाभार्थियों को योजना की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रॉसफर की जाती है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को सीधे लाभान्वित करना है, जिससे आने वाले समय में राज्य के भीतर लाखों नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों का जाल बिछाया जा सके। योजना के तहत पात्रता के लिए आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। आगरा जनपद में इस दृढ़दर्शी योजना के जमीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन और इसके सकारात्मक प्रभाव का एक उत्कृष्ट उदाहरण गोकुलपुरा निवासी श्री कृष्णा यादव हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के कारण उनके लिए ऑफ बड़ौदा, आगरा शाखा द्वारा 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और सरकार की सपना देखते थे, लेकिन पूंजी की कमी उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। इसी दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी मिली। उन्होंने योजना का अध्ययन किया

और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए केनरा बैंक, सिकंदरा-बोदला रोड शाखा, आगरा से 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त किया। इस वित्तीय सहायता से कृष्णा यादव ने कार्डबोर्ड उद्योग की स्थापना की। शुरुआत में बाजार की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनकी लगातार मेहनत और गुणवत्ता ने उनके व्यवसाय को सफलता की राह पर आगे बढ़ाया। आज उनकी इकाई सुचारु रूप से संचालित हो रही है और उन्होंने अपने साथ दो अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। इसी तरह आगरा के ही खातीपाड़ा, लोहमंडी के निवासी श्री परवीन अली ने भी इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान दी है। वे लंबे समय से स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत आवेदन करने पर उनकी पात्रता के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, आगरा शाखा द्वारा 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और सरकार की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। प्राप्त वित्तीय सहायता से परवीन अली ने कारपेट उद्योग से संबंधित अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। आधुनिक संसाधनों और बेहतर प्रबंधन के साथ उन्होंने अपने

यह अभियान उत्तर प्रदेश को 'वन ट्रिलियन डॉलर' की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प को गति देने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं का पलायन थमा है और स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है। इसी कड़ी में आगरा जनपद में इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत प्रभावी ढंग से हो रहा है, जहां जिला प्रशासन और स्थानीय बैंक शाखाओं के सक्रिय सहयोग से युवाओं के सपने तेजी से साकार हो रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशिष्ट वित्तीय संरचना है, जो नए उद्यमियों के लिए शुरुआती जोखिम को काफी कम कर देती है।

कार्य को आगे बढ़ाया और आज उनकी इकाई सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने व्यवसाय के माध्यम से उन्होंने 4 अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे पूरा नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत आवेदन करने पर उनकी पात्रता के आधार पर बैंक ऑफ बड़ौदा, आगरा शाखा द्वारा 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और सरकार की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया। प्राप्त वित्तीय सहायता से परवीन अली ने कारपेट उद्योग से संबंधित अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। आधुनिक संसाधनों और बेहतर प्रबंधन के साथ उन्होंने अपने

तय लक्ष्यों में और अधिक वृद्धि करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जिले के अधिक से अधिक युवाओं को इस कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। वित्तीय सहायता के साथ-साथ यह अभियान युवाओं की व्यावसायिक क्षमता को निखारने पर भी पूरा ध्यान केंद्रित करता है। ऋण प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण की अनिवार्यता यह सुनिश्चित करती है कि जो भी उद्यम शुरू हो, वह बाजार की व्यावहारिक समझ के साथ आगे बढ़े। डिजिटल साक्षरता और आधुनिक व्यापारिक तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने न केवल युवाओं के सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि प्रदेश की देश के एक प्रमुख स्टार्टअप और उद्यमशीलता केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ठोस नींव रख दी है। बिना गारंटी का यह ब्याज मुक्त ऋण युवाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखा रहा है। सरकारी सहायता, जिला प्रशासन के मार्गदर्शन, बैंक अधिकारियों के सहयोग और युवाओं के दृढ़ संकल्प के बल पर आज प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहा है।

जनपद- आगरा

ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना : श्रमिक रमेश की बेटी की धूमधाम से हुई शादी

गरीब परिवारों में बेटी की शादी हमेशा एक बड़ी चिंता का विषय रही है। देहेज, बारात और अन्य खर्चों का बोझ अक्सर माता-पिता को कर्ज के जाल में फंसा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना ऐसे ही गरीब श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने हजारों श्रमिकों की बेटीयों के हाथ पीले करवाकर उनके सम्मान की रक्षा की है। कानपुर नगर के जाजमऊ क्षेत्र के एक कारखाने में काम करने वाले रमेश प्रसाद की कहानी भी इसी बदलाव की गवाह है। रमेश प्रसाद पिछले 15 वर्षों से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत एक चमड़ा फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी मासिक मजदूरी 18,000 रुपये है। इस सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बड़ी बेटी सीमा की शादी की उम्र होने पर रमेश की चिंता बढ़ गई थी।

बेटी की शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यह सोचकर उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। साहूकार से कर्ज लेता तो पूरी जिंदगी ब्याज भरते निकल जाती। इसी दौरान रमेश को फैक्ट्री के श्रमिक कल्याण अधिकारी से ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के बारे में पता चला। अधिकारी ने बताया कि यदि श्रमिक की मासिक मजदूरी 24,000 रुपये से अधिक न हो तो उसकी पुत्री की शादी के लिए सरकार 51,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देती है। यह रमेश प्रसाद की कहानी भी इसी बदलाव की गवाह है। रमेश प्रसाद पिछले 15 वर्षों से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत एक चमड़ा फैक्ट्री में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनकी मासिक मजदूरी 18,000 रुपये है। इस सीमित आय में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बड़ी बेटी सीमा की शादी की उम्र होने पर रमेश की चिंता बढ़ गई थी।

पर मिलने से रमेश का बड़ा बोझ हल्का हो गया। श्रमिक श्री रमेश ने बताया कि सरकार से मिली इस मदद से मैंने बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदा, बारातियों के खाने-पीने का इंतजाम किया और बिना किसी कर्ज के शादी संपन्न कराई। रमेश की बेटी सीमा की शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बारात आई, झरनार हुआ, कन्यादान हुआ और बेटी हंसी-खुशी विदा हुई। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि एक मामूली श्रमिक की बेटी की शादी इतने अच्छे से कैसे हो गई।

रमेश गर्व से कहते हैं, आज मेरी बेटी संसार में खुश है। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के जवाब में संभव हुआ है। अगर यह योजना न होती तो शायद मैं बेटी की शादी इतनी इज्जत से नहीं कर पाता। रमेश की पत्नी सुनीता देवी भावुक होकर कहती हैं, हम गरीबों के लिए बेटी की शादी सबसे

योजना के तहत पात्रता की जांच के बाद रमेश का आवेदन स्वीकृत हो गया। बेटी की शादी की तारीख तय होते ही श्रम विभाग द्वारा 51,000 रुपये की धनराशि सीधे रमेश के बैंक खाते में भेज दी गई। यह राशि समय पर मिलने से रमेश का बड़ा बोझ हल्का हो गया। श्रमिक श्री रमेश ने बताया कि सरकार से मिली इस मदद से मैंने बेटी के लिए जरूरी सामान खरीदा, बारातियों के खाने-पीने का इंतजाम किया और बिना किसी कर्ज के शादी संपन्न कराई। रमेश की बेटी सीमा की शादी पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम से हुई। बारात आई, झरनार हुआ, कन्यादान हुआ और बेटी हंसी-खुशी विदा हुई। मोहल्ले के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि एक मामूली श्रमिक की बेटी की शादी इतने अच्छे से कैसे हो गई।

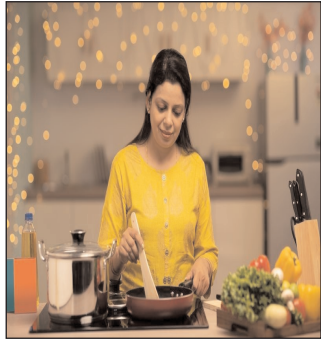
बड़ा सपना और सबसे बड़ा डर दोनों होता है। सरकार ने हमारी बेटी का कन्यादान कर के हमारा डर खत्म कर दिया। अब हम दूसरी बेटी की शादी के लिए भी निश्चित हैं। सरकार ने हम जैसे श्रमिकों को सच में सहायता दी है। ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना प्रदेश के लाखों पंजीकृत कारखाना श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है। सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित ज्योतिबा

फुले श्रमिक कन्यादान योजना के अंतर्गत 24,000 रुपये से कम मासिक आय वाले श्रमिकों को पुत्री के विवाह हेतु 51,000 रुपये की सहायता देती है। यह योजना साबित करती है कि सरकार श्रमिकों के सुख-दुख में साथ खड़ी है। रमेश की बेटी की हंसी और उनके परिवार का सम्मान ही ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना की सबसे बड़ी सफलता है।

-सोनी सिंह, सूचना अधिकारी

घरेलू श्रम को सम्मान से मातृशक्ति को मिलेगी प्रतिष्ठा

भारतीय समाज में गृहिणियों को हमेशा से परिवार की धुरी माना जाता रहा है, किंतु घरेलू कार्यों में उनके अथक योगदान के बावजूद वे कभी आर्थिक विमर्श का केंद्र नहीं रहीं। इसी संदर्भ में हाल ही में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली गृहिणियों के मुआवजे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया कि घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके श्रम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महिलाओं के घरेलू कार्यों की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 17 प्रतिशत हिस्सेदारी मानी जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से किसी गृहिणी के योगदान को नजरअंदाज करना ही एक अमान्यता है।



योगदान का मूल्य आंका जाना बेहद जरूरी है, दरअसल ,यह फैसला घरेलू श्रम को सम्मान और पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही यह उस

रूढ़िवादी सोच पर भी प्रहार है, जो महिलाओं के अवैतनिक श्रम को अनुत्पादक मानती रही है। दरअसल भारतीय समाज में एक अजीब भ्रम लंबे समय से रहा है कि घर अपने आप चलता है। रसोई में खाना खुद बनाते हैं, बच्चे अपने आप बड़े हो जाते हैं और कपड़े खुद धुल जाते हैं। लेकिन असल में इस चमत्कारी का नाम है गृहिणी। उसे हर काम करते हुए देखा जाता है, किंतु कमाते हुए नहीं माना जाता। बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस भ्रम को तोड़ा था। जब अदालत ने कहा कि नौकरी न करने वाली पत्नी को 'बेकार' नहीं कहा जा सकता। यह केवल कानूनी टिप्पणी नहीं, बल्कि सामाजिक आईना है। इसमें वह

चेहरा साफ दिखाता है, जिसे समाज देखने से बचता रहा है। एक गृहिणी का श्रम भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अदृश्य स्तंभ है। हालांकि वे अर्थव्यवस्था से भी स्पष्ट होता है कि घरेलू श्रम का आर्थिक महत्व बेहद बड़ा है।

भारत के 2024 के समय-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं प्रतिदिन औसतन 305 मिनट (करीब 5 घंटे) अवैतनिक घरेलू सेवाओं में लगाती हैं, जबकि पुरुष औसतन 98 मिनट ही देते हैं। वे परिवार के सदस्यों की देखभाल जैसे अवैतनिक देखभाल कार्यों में भी पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं। दूसरी ओर, 2024 की वैश्विक

लैंगिक अंतर रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रमबल भागीदारी में सुधार के बावजूद वेतनयुक्त कार्यों के साथ-साथ घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ बना हुआ है। साल 2024 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भी पाया गया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गृहिणियां भोजन बनाना, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, सफाई, पानी और अन्य घरेलू प्रबंधन जैसे कार्यों में प्रतिदिन कई घंटे लगती हैं, जिनका बाजार मूल्यांकन किया जाए तो परिवारों को इसके लिए बड़ी राशि खर्च करनी पड़े। अनेक अर्थशास्त्री मानते हैं कि यदि अवैतनिक घरेलू श्रम को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाए।

पारिवारिक त्याग की अनदेखी कर आज़ादी की चाह

फरीदाबाद में राहुल नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने वीडियो बनाया और कहा कि वह घर के सारे काम करता है, व्यापार भी करता है, फिर भी उसकी पत्नी उसे मारती-पीटती है। दूसरा किस्सा पुणे के केतन का है, कहा गया कि उसकी मंगेतर सिया ने अपने मित्र चेतन की मदद से उसे लोहागढ़ पहाड़ी से धक्का दे दिया। सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि केतन के सिर पर बाल नहीं थे और वह हकलता था। इन दोनों मामलों में युवाओं ने जान गंवाई। इनके घर वालों, परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं। मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा-हा-हा करके वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में न इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी जब हम



अधिकारों की बात करते हैं, तो उनका अर्थ होता है 'जोवन, बड़े की भावना को खत्म करने की बात होती है। लेकिन मृत्यु पर परिजनों पर क्या गुजरी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। मगर अफसोस की बात ये है कि इन दोनों की मृत्यु को स्त्री अधिकारों के नाम पर सेलिब्रेट किया गया। कहा गया कि अब तक स्त्रियां सहती रही हैं, मगर अब वे बदला ले रही हैं। मुस्कान सोनी नाम की दांतों की डॉक्टर ने तो बाकायदा केतन की मौत का मजाक उड़ाया कि उसके साथ तो ऐसा होना ही था और हा-हा-हा करके वीडियो पोस्ट किया। हालांकि बाद में न इस डॉक्टर ने माफी भी मांगी जब हम

हैं। ऐसा कहने वाले वे लोग हैं, जो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति वाले हैं। जिनके ईर्द-गिर्द सेवकों और सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज है, लेकिन ज्ञान वे उन आम लड़कियों को दे रहे हैं, जो अमूमन अपराध की जद में होती हैं। 'अपनी सुरक्षा अपने हाथ' वाली कलावत इन पर चरितार्थ होती है। फिर देर रात तक पाटी करना या शराब पीना आम लड़कियों का जीवन नहीं है। और क्या स्त्रियों के लिए शराब पीना इतनी अच्छी होता है। फिर ऐसा क्यों है कि अक्सर महिलाएं अपने घर के आसपास शराब के ठेके खुलने का विरोध करती हैं। शराबबंदी की मांग करती हैं क्योंकि शराब के कारण ही उनके पति तरह-तरह की हिंसा करते हैं। यदि वे पैसे भी कमाएं, तो उनके पैसे शराब पीने के लिए खीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गांधी जी लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। न वे अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात लौट सकती हैं, न शराब पी सकती

स्वास्थ्य भी खराब होता है। यदि इन लोगों की मानें तो देश में चलने वाले जितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन 'माई लाइफ और माई च्वाइस' का विचार एलीट स्त्री-पुरुषों के मन में इतना बसा हुआ है कि वे अपनी शर्तों को दूसरों के लिए खीन लिए जाते हैं। उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गांधी जी लिए सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि हमारे परिवारों का ढांचा जिम्मेदार है। जहां लड़कियों को कुछ करने की आजादी नहीं। न वे अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं, न देर रात लौट सकती हैं, न शराब पी सकती

संसाधन भी खुद जुटाए। माता-पिता की जमीन-जायदाद में भी हिस्सा मत मांगिए। बीमारी-हारी में भी अपनी मदद खुद कीजिए। ड्रीम वैडिंग करना हो, तो खुद पैसे जुटाइए। उनके सम्पर्कों का भी लाभ मत उठाइए।अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजादी के नाम पर कीमत कोई चुकाना नहीं चाहता। हम कीमत बात न हो, तो हत्या की जा सकती है। अतिवादी लोग इसे जायज ठहराने के लिए झंडा बुलंद कर सकते हैं। विदेश में लोन लेकर पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता इस कर्ज को नहीं मिलते। सिर्फ कर्तव्य ही नहीं, अधिकारों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। लेकिन आजा

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विदाई एवं सम्मान समारोह संपन्न

अपने कृत्यों और दायित्वों को निभाने में कोई विलम्ब न करें - संतोष कुमार मिश्रा वरिष्ठ प्रवक्ता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ तथा पूर्व माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ खैराबाद के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र की पदोन्नति एवं रायबरेली के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर स्थानांतरण के अवसर पर विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित, प्रवक्ता मनीष पांडेय, जिला उपाध्यक्ष प्राथमिक वंदना दीक्षित, डॉक्टर अनुपम मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष जूनियर नरेश मिश्रा, प्राथमिक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, संरक्षक बृजेन्द्र कुमार टी पी सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजिम हुसैन सिद्दीकी,



राज्य पुरस्कार प्राप्त नीलम कुमारी, ए आर पी संजीव पट्टेरिया, वीरेन्द्र कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक योगेन्द्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर मालार्पण एवं द्वीप प्रज्वलित करके पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र एवं अन्य ने किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि का माल्यार्पण तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तथा सरस्वती वंदना रबीना बानो, नीलम कुमारी, शशि बाला ने कराई, ज्ञात हो कि संतोष कुमार मिश्र ने खैराबाद ब्लॉक में 2 अगस्त 2024

नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा को महापौर सुषमा खर्कवाल ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने शनिवार को उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने मंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर जनसेवा के लिए मंगलकामनाएं व्यक्त कीं। इस अवसर पर नगर निगम लखनऊ के कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एवं पार्षद दल के उपमंडा सुशील तिवारी 'पम्मी' सहित कई पार्षद भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने मंत्री ए.के. शर्मा को जन्मदिन की बधाई

संक्षिप्त खबरें

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, बूथ सशक्तीकरण पर रहेगा पूरा फोकस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों, बूथ सशक्तीकरण और जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष धर्मच चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) भूपेन्द्रपाल सिंह ने नई कार्यकारिणी तथा विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाने पर जोर दिया। पार्टी ने प्रत्येक बूथ को भाजपा की जीत का मजबूत आधार बनाने और विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने का निर्णय लिया।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता आयु लगभग 49 वर्ष पुत्र स्वो 0 सिया राम गुप्ता, निवासी 543/85 पीएन-78बी, संगम नगर, कसमारी बाग, मल्हपुर, राजाजीपुर, लखनऊ, 30300- 226017 मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी एवं भारतीय नागरिक है। मेरी पुत्री शुभी गुप्ता (Shubhi Gupta) ने हाईस्कूल की परीक्षा COUNCIL FOR THE INDIAN SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATIONS, NEW DELHI से सन् 2026 में उत्तीर्ण की थी। जिसका यूनिफ़ आई0डी0 (रजि0 नंबर)-8779035 व अनुक्रमांक- 1268196 है। यह कि शपथी की पुत्री के हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र में उसकी माता का नाम ज़ुटिविश KUSHBOO GUPTA अंकित हो गया है। कुशबोव शपथी की पुत्री की माता का सत्य, सही व वास्तविक नाम KHUSHBOO GUPTA है, जो कि शपथी की पुत्री की माता के आधार कार्ड में अंकित है। अपनी पुत्री के उक्त वर्णित हाईस्कूल के अंक प्रमाण-पत्र में अपनी पुत्री की माता का नाम KUSHBOO GUPTA के स्थान पर KHUSHBOO GUPTA अंकित करवाना चाहता है। जो कि शपथी की पुत्री की माता का सत्य, सही व वास्तविक नाम है।

सीतापुर, लखनऊ, आस-पास

साहित्य सृजन संस्थान, बिसवां द्वारा जरूरतमंद, मेधावी बच्चों को निःशुल्क वितरित की गई पाठ्य पुस्तकें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर) शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक सरोकारों को समर्पित अ. भा. संस्था 'साहित्य सृजन संस्थान' द्वारा क्षेत्र बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए बिसवां में निकट पशु चिकित्सालय, तहसील रोड पर स्थापित 'सृजन पुस्तकालय' में (हाई स्कूल इंटर के छात्र, छात्राओं को) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका, चेयरमैन, पुष्प जायसवाल उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा उन्हें अंगवस्त्र, स्मृतिचिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाजसेवी गिरिधर अग्रवाल, सौरभ बंसल के द्वारा कृष्णा देवी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं को उनकी पाठ्यक्रम की पुस्तकें, स्टेशनरी और स्कूल बैग प्रदान किया गया। इसी क्रम में कुछ अन्य बच्चों को उनकी स्कूल किट उनके विद्यालय भेजी गई। इस अवसर चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकालय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और एक प्रबुद्ध पाठक वर्ग का निर्माण करते हैं। सृजन पुस्तकालय का



यह प्रयास सराहनीय है। हमारी शुभकामनाएं और भरपूर सहयोग संस्थान को सदैव सुलभ रहेगा। संस्थान के संस्थापक /अध्यक्ष साहित्यकार संदीप मिश्र सरस ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र के मेधावी जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बुक किट उपलब्ध कराई जाती है। ये बच्चे अपनी मेधा के बल पर सफलता अर्जित करके बिसवां का नाम पूरी दुनिया में जब रोशन करेंगे तो हमारे संस्थान का संकल्प सार्थक हो जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, उप प्रधानाचार्य उषा मिश्रा, गंगा स्वरूप मिश्र, एडवोकेट मनोज गुप्ता, श्रीकांत मिश्रा, नीरज मिश्रा सभासद, हरिशंकर त्रिवेदी मुकुंद पांडेय, अमन बाजपेई आदि एवं बच्चों के

अभिभावक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक दार्शनिक पुस्तकों के साथ-साथ पर्याप्त कंपटीशन बुक्स की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष विभिन्न महाविद्यालयों के अन्याय शोध छात्र छात्राएं पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध पुस्तकों से अपने लघु शोध प्रबंध तैयार करते हैं। सृजन पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर बच्चों को विभिन्न स्कूल, कॉलेज सेंटर में एडमिशन एवं छूट का सहयोग दिलाया जाता है और छात्र-छात्राओं के लिए मोटिवेशनल क्लासेस एवं करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। अब पुस्तकालय में कंप्यूटर सभासद, हरिशंकर त्रिवेदी मुकुंद पांडेय, अमन बाजपेई आदि एवं बच्चों के

बीजेएसपी जिला अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया आक्रोश

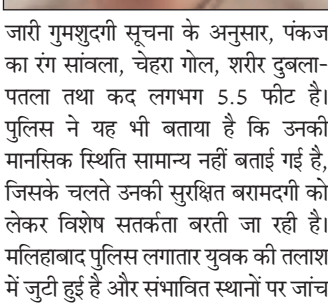
अभियुक्त महेन्द्र सोनी के खिलाफ डीजीपी, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम और SP बांद्रा को भेजा पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने आज बताया कि जिला बांद्रा के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को कुछ अराजक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज दिनांक 11.07.2026 को सुबह 9:35 बजे जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंड जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा।

इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS केंद्र के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश को सूचना दी जा रही है। आज दिनांक 11.07.2026 को सुबह 9:35 बजे जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंड जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा।

इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS केंद्र के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश को सूचना दी जा रही है। आज दिनांक 11.07.2026 को सुबह 9:35 बजे जिला अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंड जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा।



जारी गुमशुदगी सूचना के अनुसार, पंकज का रंग सांवला, चेहरा गोल, शरीर दुबला-पतला तथा कद लगभग 5.5 फीट है। पुलिस से यह भी बताया है कि उनकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई गई है, जो जिसके चलते उनकी सुरक्षित बरामदगी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मलिकाबाद पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है और संभावित स्थानों पर जांच

अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने फोन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी कि जब वे गांव स्योंड जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि 'मरवा जाओगे, ऐ होगा वो होगा। इस गंभीर मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह ने कहा कि पार्टी पहले ही इस संबंध में अभियुक्त महेन्द्र सोनी निवासी मुंबई कथित RSS केंद्र के विरुद्ध शिकायत पत्र तैयार कर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त मुंबई, नोडल अधिकारी साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश अधीक्षक बांद्रा को सूची पोस्ट के माध्यम से भेज चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह का बयान: BJP के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने शिकायत पत्र सभी बड़े अधिकारियों को भेज दिया है। महेन्द्र सोनी और उसके आदमी जिला अध्यक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर जिला अध्यक्ष को एक खरोंच भी आई तो BJP पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पुलिस प्रशासन से मांग है कि 24

सीडीपोस्ट के माध्यम से भेज चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बृज मोहन सिंह का बयान: BJP के कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने वाले चाहे कितने भी बड़े हों, हम डरने वाले नहीं हैं। हमने शिकायत पत्र सभी बड़े अधिकारियों को भेज दिया है। महेन्द्र सोनी और उसके आदमी जिला अध्यक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अगर जिला अध्यक्ष को एक खरोंच भी आई तो BJP पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। पुलिस प्रशासन से मांग है कि 24

काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुरांग नहीं मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आमजन से सहयोग की अपील की है। मलिकाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार, पंकज 5 जुलाई की रात करीब 12 बजे से लापता है। उनका पता मोहल्ला बस्ती धनवन्तराय कटवा, थाना मलिकाबाद, जनपद लखनऊ बताया गया है।

काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुरांग नहीं मिलने पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आमजन से सहयोग की अपील की है। मलिकाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार, पंकज 5 जुलाई की रात करीब 12 बजे से लापता है। उनका पता मोहल्ला बस्ती धनवन्तराय कटवा, थाना मलिकाबाद, जनपद लखनऊ बताया गया है। परिसरों ने पहले अपने स्तर पर रिसर्चेदारों, परिचितों और आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा

मुख्यमंत्री योगी के संभावित आगमन से गोविंद साहब धाम में हलचल तेज, तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आलापुर, अंबेडकरनगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आलापुर सुस्थित विधानसभा क्षेत्र स्थित महात्मा गोविंद साहब के संभावित दौरों को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यदि गोविंद साहब धाम पहुंचते हैं तो माना जा रहा है कि वह संत परंपरा और सामाजिक समरसता का संदेश देने के साथ-साथ क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि महात्मा गोविंद साहब की तपोस्थली का व्यापक कायाकल्प कराया जाएगा तथा इसे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में विकसित करने की दिशा में बड़ा निर्णय



लिया जा सकता है। क्षेत्रवासियों को यह भी आशा है कि पूर्वांचल के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध गोविंद साहब मेलों को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान करने की घोषणा हो सकती है। वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरी होने से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलने के साथ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के साथ रामनगर, कटेहरी और भीटी बाजार को नगर पंचायत बनाए जाने की चर्चाएं भी तेज हैं। विशेष रूप से रामनगर को नगर पंचायत बनाए जाने की सभी आवश्यक काजगी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शासन स्तर पर अंतिम स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के संभावित दौरों के दौरान इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

नई रणनीति के साथ विधानसभा चुनावी मैदान में उतरी सपा, हर बूथ पर तैयार होंगे 50 डिजिटल योद्धा

लखनऊ। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) ने प्रदेशव्यापी घर-घर संपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर जिला एवं शहर इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके जरिए सपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के साथ-साथ डिजिटल नेटवर्क का भी विस्तार करेगी। पार्टी की रणनीति के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सुनिश्चित की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया का पाठदर्शी बनाने के लिए सभा मेंला स्थलों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था होगी। सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती तथा पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। मिशन निर्देशक ने बताया कि प्रत्येक रोजगार मेले के समापन के बाद संबंधित जिला प्रशासन चयनित एवं नियुक्त युवाओं की अंतिम रिपोर्ट मिशन मुख्यालय को भेजेगा, ताकि रोजगार उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की प्रभाव निगरानी की जा सके।



यूएफसी इवेंट पर हमले की साजिश का खुलासा

वाशिङ्गटन, डी.सी. (ए.एन.सी.)। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' में जून में आयोजित 'यूएफसी केज-फाइटिंग' कार्यक्रम पर झूठे और स्थावर हमले की कथित साजिश में संलिप्तता को लेकर बृहस्पतिवार को आठ लोगों पर हत्या और आतंकवाद संबंधी षड्यंत्र के आरोप लगाए गए। यूएफसी द्वारा आयोजित इस मिश्रित मार्शल आर्ट्स मुकाबले में लड़ाकू एक लोहे की जाली से चुरे अष्टकोणीय पिंजरे के अंदर मुकाबले करते हैं। ओहायो में दायर अभियोग में सभी आठ आरोपियों पर दो अलग-अलग साजिशों का आरोप लगाया गया है। पहला आरोप आतंकवादियों को सहायता उपलब्ध कराने की साजिश और दूसरा आरोप संघीय सरकारी क्षेत्र में हत्या करने एवं एक संघीय सरकारी अधिकारी की हत्या करने की साजिश है। नए अभियोग के अनुसार, इस साजिश की शुरुआत मई में हुई थी, जब इस समूह ने धन, आगवनीस्र, गोला-बारूद, बलेटप्रुफ



जैकेट, विस्फोटक, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण, संचार उपकरण और अन्य सामान इकट्ठा करना शुरू किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूएफएस की केज-फाइटिंग कार्यक्रम पर सभावित खतरे की 10 जून को जानकारी मिली। यह मिश्रित मार्शल आर्ट्स कार्यक्रम 14 जून को आयोजित होना था। अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले महीने यूएफएस कार्यक्रम पर कथित साजिश के संबंध में देश के अलग-अलग हिस्सों को ओहायो,

मिसौरी, वाशिंगटन, नेब्रास्का और कैलिफोर्निया में कई अपराधिक शिकायतों की घोषणा की थी। बृहस्पतिवार को घोषित यह अधियोग सरकार की ओर से पूरे मामले के एक साथ जोड़कर आहवायों में एक ही मुकदमे के रूप में चलाने का प्रयास है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का उद्देश्य हमले के जरिए सरकार को अस्थिर करना था। संघीय हलफनामे के अनुसार, आरोपियों में से एक ने जाचकर्ताओं को बताया कि उनकी योजना विस्फोटकों से

अमेरिकी न्याय विभाग ने पिछले महीने यूएफसी कार्यक्रम पर कथित साजिश के संबंध में देश के अलग-अलग हिस्सों ओहायो, मिसौरी, वाशिंगटन, नेब्रास्का और कैलिफोर्निया में कई आपराधिक शिकायतों की घोषणा की थी। बृहस्पतिवार को घोषित यह अभियोग सरकार की ओर से पूरे मामले को एक साथ जोड़कर ओहायो में एक ही मुकदमे के रूप में चलाने का प्रयास है।

लदे ड्रोन कार्यक्रम स्थल पर उड़ाने और उसके बाद भगदड़ मचने पर भाग रहे लोगों पर स्नाइपर से गोलीबारी करने की थी।

140 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन तैयार, मिलेगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

हेरिटेज वास्तुकला के साथ आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित स्टेशन बनेगा पश्चिमी राजस्थान की नई पहचान



व्यापार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि स्टेशन का नया मुख्य भवन जी-2 संरचना में करीब 8,327 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। भवन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पथर का उपयोग किया गया है, जिससे स्टेशन को शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप भव्य हेरिटेज स्वरूप मिला है। विशाल प्रवेश और निकास द्वार इसकी आकर्षक पहचान को और मजबूत बनाते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 10 लिफ्ट, 10 एक्सेलेटर, छह मीटर चौड़ाई वाले दो फुट ओवरब्रिज, विशाल

एयर कॉनकोर्स, आधुनिक प्रतीक्षालय, विस्तृत सर्कुलेंटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएँ तथा 480 वर्गमीटर का वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके अलावा तीनों प्लेटफॉर्मों पर 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में आधुनिक शेड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को हर मौसम में बेहतर सुविधा मिलेगी। रेलवे ने पर्यटन सीजन में बढ़ने वाली यात्री संख्या को देखते हुए एस्टेशन की प्रमुख वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का सफलतापूर्वक आउटडोरसिंग भी कर दी है। स्टेशन परिसर में कैफे/स्क, रिटायरिंग रूम, डॉर्मेटरी, एयर कॉनकोर्स से जुड़े वेटिंग लाउज, मल्टी-पर्पज हॉल और आधुनिक वाहन पार्किंग

जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा स्टेशन पर रेल कोक रेपेटेंट और आधुनिक कैटरिंग स्टॉल भी स्थापित किया गया है। रेलवे के अनुसार रेल वाणिज्यिक परिसरपंतिथियों के प्रभावी उपयोग से प्रतिवर्ष करीब 50 लाख रुपये की गैर-किराया आय होने का अनुमान है, जिससे रेलवे के राजस्व में वृद्धि के साथ यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। रेलवे अंतर्गत एकता का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह पुनर्विकसित स्टेशन न केवल देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि जैसलमेर के पर्यटन व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

पुष्कर जोग ने यूके में अपनी नई हिंदी फिल्म 'अंतराल' की शूटिंग शुरू की

मुंबई एक्टर पुष्कर जोग इन दिनों अपनी आने वाली हिंदी फिल्म 'अंतराल' की शूटिंग के लिए यूनाइटेड किंगडम में हैं, और इस बार कहानी में हैं प्यार भी... और खतब भी। पुष्कर ने सोशल मीडिया पर सेट से क्लैपबोर्ड की एक झलक शेयर करते हुए इस नए सफर की शुरुआत की अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, 'यूनाइटेड किंगडम में सेट अपनी अगली हिंदी हॉरर रोमांटिक ड्रामा फिल्म की घोषणा करते हुए उत्साहित हूं। यह एक ब्रिटिश इंडियन क्रॉसओवर फीचर फिल्म 'अंतराल' है, जिसमें मैं और @anissaniam हैं।' इस फिल्म में पुष्कर जोग के साथ अनिसा बट नजर आएंगी। फिल्म को गुजबंस्प एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इसे ब्रिटिश इंडियन फिल्ममेकर तेजा सलानी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी निखिल रानादे संभाल रहे हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले पुष्कर हमेशा ऐसे किन्नदार चुनते हैं जो उन्हें रचनात्मक रूप से चुनौती देते, और 'अंतराल' भी उसी कड़ी की एक दिलचस्प नई पेक्कड़ है। पुष्कर



यह एक ब्रिटिश इंडियन कॉरपोरेशन फीचर फिल्म 'अंतराल' है, जिसमें मैं और @anisanian हैं। इस फिल्म में पुष्कर जोग के साथ अनीसा वतनर आएंगी। फिल्म को गूजबॉस एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि इसे ब्रिटिश इंडियन फिल्ममेकर तेजा सलानी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी निखिल रानादे संभाल रहे हैं। भारतीय सिनेमा में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले पुष्कर हमेशा ऐसे किटार चुनते हैं जो उन्हें रचनात्मक रूप से चुनौती दें, और 'अंतराल' भी उसी कड़ी की एक दिलचस्प नई पेशकश है।

के इस नए अपडेट पर फैस और इंडस्ट्री दोनों की तरफ से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हर कोई इस फ्रेश और दिलचस्प फिल्म का बेसबी से

इंतजार कर रहा है। यूके में शूटिंग जारी है, और उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में फिल्म से जुड़ी और भी रोमांचक डिटेल्स सामने आएंगी।

15 साल बाद मार्वल स्टेडियम से अलग की मेलबर्न रेनेगोड्स ने राहें, एमसीजी होगा नया घरेलू मैदान

मेलबर्न । बिग बैश लीग (बीबीएल) की प्रेचंडाईजी मेलबर्न रेनेगेड्स ने अपनी पुरुष टीम के घरेलू मैदान को बल्लेने का फैसला किया है। मेलबर्न रेनेगेड्स ने 15 साल के बाद मार्वेल स्टेडियम से अपनी खेल आसल कर ली हैं। आगामी सीजन में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) रेनेगेड्स का घरेलू मैदान होगा। बीबीएल क्लब ने मुक़द़्दर को इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। मेलबर्न रेनेगेड्स ने बिग बैश लीग की शुरुआत 2011-12 सीजन से की थी और तब से वह अपने ज्यादातर घरेलू मुक़ाबले मार्वेल स्टेडियम में खेलती आ रही थी। इसी बड़ा पर टीम ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। रेनेगेड्स ने बीबीएल के आठवें सीजन में खिताब जीता था और उस यादगार सफ़र का गवाह भी मेलबर्न स्टेडियम ही बना था। अब क्लब ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब (एमसीजी) के साथ नया समझौता किया है, जिसके तहत बिग बैश लीग के 16वें सीजन से टीम के कुछ ख़ास मुक़ाबले एमसीजी में खेले जाएंगे। आगामी सीजन में रेनेगेड्स एमसीजी में कुल तीन मैच खेलेगी। इनमें दो मुक़ाबले एमसीजी में खेले जाएंगे।



धरौली टीम के रूप में खेलेगी, जिसमें मेलबर्न डर्बी भी शामिल होगा। इसके अलावा एक मैच वह मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ मेहमान टीम के रूप में खेलेगी। रेगिडोर इस सीजन में मेलबर्न के जंक्शन ओवल मैदान पर भी अपने दो धरौली मुकाबले खेल सकती है। इससे अलावा टीम दिसंबर में होने वाले ऐतिहासिक चेन्नई मुकाबले का भी हिस्सा बनेगी। इस बदलाव के चलते जिलाओं में पिछले पांच सालों में पहली बार कोई बिग बैश मैच नहीं खेला जाएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सीओ स्टुअर्ट फॉक्स ने इस बदलाव को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि 2026-

27 की गर्मियों में एमसीजी का क्रिकेट कार्यक्रम और बढ़ा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग गर्मियों के क्रिकेट कैलेंडर का अहम हिस्सा है और क्लब रेनेगेड्स के स्वतंत्र के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि एमसीजी में फैस को रोमांचक मुकाबलों का आनंद लेने के और ज्यादा मौके मिलेंगे। रेनेगेड्स के कप्तान विल सदरलैंड ने भी एमसीजी में खेलने को लेकर खुशी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध खेल स्थलों में से एक है और हर खिलाड़ी वहां खेलने का सपना देखता है। उन्होंने पिछले सीजन में एमसीजी पर द्रष्टा

डब्ली मुकाबले का जिज्ञा करते हुए कहा कि वहां का माहौल शानदार था और इससे पता चलता है कि इस मैदान पर बिग बैश क्रिकेट कीतना खास हो सकता है। सदरलैंड ने कहा कि टीम के खिलाड़ी भारी बीड के सामने खेलने और अपने फैस के साथ यादगार पल बनाने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने यह भी माना कि टीम के समर्थकों के लिए यह बदलाव आसान नहीं रहा होगा, लेकिन खिलाड़ी नई शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मेलबर्न रेनेगेड्स के जनरल मैनेजर मैक्स एबॉट ने कहा कि एमसीजी पर क्रिकेट खेलना मेलबर्न की गर्मियों का पहलू है। उन्होंने कहा कि टीम दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियमों में से एक में अपने घरेलू मुकाबले खेलने को लेकर रोमांचित है। हालांकि, उन्होंने मार्वल स्टेडियम की भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह मैदान पिछले 15 वर्षों से रेनेगेड्स की पहचान का हिस्सा रहा है। टीम ने यह कई यादगार मुकाबले खेले और कई खास पल बनाए। उन्होंने कहा कि मार्वल स्टेडियम हमला क्लब के इतिहास में एक विशेष स्थान रखेगा।

गौरव श्रीवास्तव ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ किया खेल सीआईए एजेंट बनकर दिया धोखा, अरबों रुपये की डिफेंस डील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। एक भारतवर्शी गौरव श्रीवास्तव ने पूरे देश की सरकार को चकमा देकर अरबों रुपये का चूना लगा दिया। दरअसल भारतीय मूल के एक कारोबारी ने कथित तौर पर खुद को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का एजेंट बताकर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के करीब आया। आरोप है कि उसका उद्देश्य अरबों डॉलर के रक्षा सौदे हासिल करना था। अर्गनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतवर्शी कारोबारी गौरव श्रीवास्तव ने खुद को सीआईए का

अधिकारी बताकर कई प्रभावशाली लोगों का भरोसा जीता और फिर उन्हें अमेरिका के साथ अरबों डॉलर के रक्षा समझौते का झांसा दिया। गौरव ने इंडोनेशियाई सेना के लिए 36 लड़ाकू विमान, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और मिलिट्री कमांड सिस्टम दिलाने के नाम पर इंडोनेशिया की सरकार को अरबों रुपये का चूना लगाया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौरव श्रीवास्तव ने इंडोनेशिया के पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबान्तो से नजदीकी संबंध बनाए। साल 2020 में वह कथित तौर पर वॉशिंगटन डीसी और जकार्ता में सुबिजायों के साथ कई उच्चस्तरीय बैठकों में शामिल हुआ, जहां लड़ाकू विमानों और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद पर चर्चा हुई

थी। इसके बाद फर्जी शेल कंपनियों के जरिए गौरव ने इंडोनेशिया से 425 करोड़ रुपये का कर्ज भी मंजूर करा लिया। ये ठगी 2020 से 2022 के बीच की गई। यह रिपोर्ट श्रीवास्तव के पूर्व कारोबारी साझेदार नील्स ट्रेस्ट द्वारा कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क की अदालतों में दायर दीवानी मुकदमों पर आधारित है। ट्रेस्ट का दावा है कि उन्होंने अपनी कंपनी में श्रीवास्तव को 50 प्रतिशत हिस्सेदारी दी थी ट्रेस्ट के अनुसार, श्रीवास्तव ने इंडोनेशिया के कई प्रभावशाली उद्योगपतियों से भी संबंध बनाए, जिनमें प्रबोवो सुबियांतो के भाई और अर्सरी गुप के चेरमैन हाशिम दजोजोहादिकुसुमो भी शामिल हैं। मुकदमे में शामिल रिकॉर्डेंडेन फोन कॉल्स के अनुसार, श्रीवास्तव ने दावा किया था कि

वह सी आएं के लिए काम करता है। आरोप है कि उसने इसी दावे के जरिए इंडोनेशिया के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल किया और सरकार की शीर्ष बैठकों तक पहुंच बना। दावा किया गया है कि धांधली से कमाए पैसों से गोरव ने लॉस एंजेलिस में दो सौ करोड़ रुपये का आलीशान बंगला खरीदा है। गोरव ने इंडोनेशिया के साथ अमेरिका की 1.32 लाख करोड़ रुपये की डिफेंस डील की। जांच में पता चला है कि गोरव की शेल कंपनियों ने ही डिफेंस डील हासिल की। बाद में टैक्स न जमा करने के चलते ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं। फिलहाल गोरव श्रीवास्तव के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है।

द्विजय सिंह का राजनीति से संन्यास, अब धर्म के लिए लड़ेंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पारी वे खेल चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है, 'मैं समातन धर्म को समझता हूँ, भाजपा, वीएचपी और आरएसएस को भी समझता हूँ। अब मेरा मिशन धर्म की रक्षा करना है, अब कोई राजनीति नहीं करूंगा, अपनी आविर्दास सात आस्था की रक्षा करनी है।' उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वह सक्रिय राजनीति नहीं करेंगे, सार्वजनिक सभाओं में भाषण नहीं देंगे और सोशल मीडिया पर भी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में यदि वह कोई यात्रा निकालेंगे, तो उसके लिए किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब उनका मकसद केवल धर्म की रक्षा और सामाजिक कार्यों के लिए योगदान देना है। दिग्विजय सिंह महाकाल मंदिर भूमि ट्रस्ट और राम

जन्म भूमि मंदिर ट्रस्ट में भारी गड़बड़ाइयों को लेकर 02 अक्टूबर से पटनाया शुरु करने वाले हैं। यात्रा उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर से शुरु होकर राममंदिर पहुंचकर समाप्त होगी।

यात्रा 1 हजार किलोमीटर के करीब की होगी। रावलों के जवाब में दिविजय सिंह ने कहा है, 'यात्रा में किसी तरह का किसी नेता को वे खुद होकर नहीं बुलायेंगे। राहुल गांधी को भी नहीं'।

उन्होंने कहा, 'उनकी यात्रा में वे मुख्य अतिथि के तौर पर उन कार सेवक संतोष दुबे को आमंत्रित करेंगे, जिन संतोष दुबे ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान चार-चार गोलीयां खाई थीं। राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटालों को लेकर जो आज पूरी मुस्तटाक के साथ बोल रहे हैं।'।

शरिया के तहत प्यूर्बर्टी की उम्र में निकाह पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन: हाईकोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल विवाह को लेकर एक ऐतिहासिक और बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) समेत देश का कोई भी पर्सनल लॉ, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के तहत लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्सनल लॉ, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले पॉक्सो एक्ट (POCSO Act, 2012) के प्रावधानों से ऊपर नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने 'रूबी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (Rubi Vs State of UP) मामले की सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने 19 अपराधों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार

कर दिया, जिन पर बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की का निकाह रुकवाने गई पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। याचिकाकर्ताओं (आरोपियों) की ओर से वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) के तहत, यदि कोई लड़की प्यूबर्टी (रजस्वला) की उम्र पर कर लेती है जिसे आमतौर पर 15 वर्ष माना जाता है तो वह निकाह के योग्य हो जाती है। उनका तर्क था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम उनके पर्सनल लॉ को प्रभावित नहीं कर सकता। अदालत ने इस दलील को सिर से खारिज करते हुए कहा: 'शरिया कानून, जो लड़की के विवाह के लिए प्यूबर्टी (रजस्वला) की उम्र को सक्षम मानता है, वह साफ तौर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। ' कोर्ट ने आगे

अदालत ने 19 आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिन पर बुलंदशहर में एक 16 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की का निकाह ठकवाने गई पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है।

जोड़ा कि देश के हर नागरिक के लिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शादी की न्यूनतम उम्र वही होगी जो बाल विवाह निषेध अधिनियम में तय की गई है। इसके अलावा, अदालत ने चेतावनी दी कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी की अनुमति दी जाती है, तो यह पाँचवें एकट का भी सीधा उल्लंघन होगा, क्योंकि विवाह और शारीरिक संबंध एक-दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 38 दोषियों की फांसी बरकरार

गुजरात हाईकोर्ट का फैसला, 11 को उम्रकैद; 18 साल पहले 70 मिनट में 21 धमाके हुए थे।

सत्यंत प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में स्पेशल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। निचली अदालत ने फरवरी 2022 में 38 दणियों को फांसी और 11 दणियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दणियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। आज जस्टिस एवाई कोमारे और समीर दवे की बेंच ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) से जुड़े लोगों की सजा को सही ठहराया। कोर्ट ने सरकार को 56 मुक्तकों के परिजन

को 10-10 लाख रुपए और 200 से ज्यादा घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि मुआवजा राशि का भुगतान 30 मार्च 2027 तक कर दिया जाए। धमाकों के बाद पुलिस ने अहमदाबाद को सभी ब्लैस्ट साइट्स और सूत्र में मिले बमों के मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज कीं। बाद में करीब 35 मामलों को मिलाकर एक बड़ा केस बनाया गए। सभी मामलों को एक साथ जोड़ने के बाद 2009 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। जांच और अदालत की सुनवाई 12 साल तक चली। करीब 80 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला। कोरोना के समय भी सुनवाई बंद नहीं हुई। प्रॉसिक्यूशन ने जज एग्रा पटेल की अदालत में 1,100 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट में 6,000 से अधिक दस्तावेज पेश किए गए। मामले में 5,47 चार्जशीट के कुल 3,47,800 पन्ने दाखिल किए गए, जबकि सिर्फ़ मुख्य चार्जशीट ही 9,800 पन्नों की थी। जांच

के दौरान पुलिस ने दावा किया कि धमाकों के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) और प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक

मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) से जुड़े लोगो का हाथ था। इसे 2000 के दशक में बनाया गया था।

यूपी पंचायत चुनाव: प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 10 जुलाई को होगा फैसला

ब्यूरो प्रयागराज। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में 10 जुलाई को पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश स्थानीय अधिकवक्ता संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति का 25 आई का आदेश सिद्धान्त के 73 वें संशोधन, पंचायत राज व्यवस्था तथा संविधि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। उपर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की सवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उपर, राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव अधिकवक्ता रौलेन्द्र कुमार सिंह पेश हुए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मामले में सहयोग के लिए अपर मुख्य सचिव ने पंचायतीराज को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने को कहा है।